

# 30 वर्ष पुराने यूका के कचरे के कलंक से मिली मुक्ति

प्रशासनिक संवाददाता  
भोपाल, 30 जून. ये मप्र और विशेष रूप से राजधानी भोपाल के लिए बड़ी बात है. 30 वर्ष से यूनियन कार्बाइड के कचरे का कलंक माथे पर लगाये राजधानी को आखिरकार उससे मुक्ति मिल गई है. इस कचरे को पीथमपुर में पूरी तरह जलाकर खत्म कर दिया गया है. ये काम 30 जून को पूरा किया गया.

लंबे संघर्ष और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार राज्य सरकार को इस कचरे के निष्पादन में कामयाबी मिल गई है. इस कामयाबी का जश्र मंगलवार को औपचारिक केबिनेट में भी मना, जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस संबंध में पूरी जानकारी मंत्रियों से साझा की और बताया कि कचरे के कलंक से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है. इस दौरान मंत्रियों ने इस बात के लिए मुख्यमंत्री को बकायादा बधाई भी दी.

उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में एक बगिया मां के नाम से नई योजना आरंभ की जा रही है. इसमें प्रदेश स्तर पर स्व-सहायता समूह की 30 हजार महिलाओं की 30 हजार एकड़ भूमि पर लगभग 900 करोड़ की लागत से



आजीविका संवर्धन के लिए 30 लाख उद्यानिकी पौधों का रोपण कर फल उद्यान विकसित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश को लगभग 100 नदियों के उद्गम स्थलों पर 10-

10 एकड़ भूमि पर 42 करोड़ रुपए की लागत से पौधों का रोपण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से 15 सितंबर तक एक पेड़ मां के नाम अभियान आयोजित होगा.

## 85 हजार से अधिक खेत तालाब बनने

जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत खेत का पानी खेत में संचित करने के उद्देश्य से प्रदेश में 85 हजार से अधिक खेत तालाबों का निर्माण किया गया. भूजल संवर्धन के लिए 1 लाख से अधिक कुओं का पुनर्भरण किया गया। पानी की अमृत बूंद को सहेजने के लिए अमृत सरोवर 2.0 के तहत 1000 से अधिक नए अमृत सरोवरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। शहरी क्षेत्र में समाज की सहभागिता से 3300 से अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन, 2200 नालों की सफाई और 4000 वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाई गईं. इसके साथ ही 40 लाख से अधिक नागरिकों ने 5000 से अधिक ऐतिहासिक/धार्मिक जल स्रोतों, बावड़ी, मंदिर तालाबों आदि की सफाई और जीर्णोद्धार में भाग लिया. अभियान के तहत 2 लाख 30 हजार जलदूतों का रजिस्ट्रेशन हुआ.

नर्मदा परिक्रमा पथ और पंचकषी यात्रा जैसे अन्य तीर्थ मार्गों का डिजिटलीकरण किया गया. अविरल निर्मल नर्मदा योजना के तहत 5600 हेक्टर क्षेत्र में पौधरोपण की योजना स्वीकृत कराकर कार्य आरंभ किया गया. वन क्षेत्रों में वन्यजीवों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2500 से अधिक तालाब, स्टॉप डैम जैसी जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया गया. प्रदेश की 15 हजार से अधिक जल संरचनाओं और जल संग्रहण संरचनाओं को राजस्व रिपोर्ट में दर्ज करने का कार्य भी अभियान के तहत किया गया.

एमएसपी पर मूंग उपार्जन के लिए 3.51 लाख मेट्रिक टन और उड़द उपार्जन के लिए 1.23 लाख मेट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. मूंग के लिए 30 जून तक 2 लाख 94 हजार किसानों ने तथा उड़द के लिए 11 हजार 495 किसानों का पंजीयन हो चुका है. पंजीयन के लिए 6 जुलाई तक अंतिम तिथि निर्धारित है. प्रदेशभर में मूंग और उड़द का उपार्जन 7 जुलाई से 6 अगस्त तक किया जाएगा.

# विजन 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एमओयू

मुख्यमंत्री से मिले आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के प्रतिनिधि

भोपाल, 1 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में प्रदेश के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के व्यक्ति विकास केंद्र के बीच मंत्रालय में एमओयू का आदान-प्रदान हुआ.

इस साझेदारी के अंतर्गत दोनों संस्थान जल संरक्षण, सतत कृषि और ग्रामीण आजीविका सुजन, ग्राम विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, गौधन संवर्धन, नशामुक्ति, स्वास्थ्य, सामाजिक और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेंगे. यह समझौता सतत विकास लक्ष्यों की



दिशा में राज्य सरकार की पहलों को सशक्त करने, पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने, नीतिगत निर्णयों में सहयोग, योजनाओं के प्रभावी मूल्यांकन और व्यापक सर्वेक्षण के माध्यम से प्रदेश की दीर्घकालिक विकास योजना

विजन 2047 के लक्ष्यों को पूर्ण करने में सहायक होगा. डॉ. यादव की उपस्थिति में समझौता पत्र आदान-प्रदान के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी संजय शुक्ला, मप्र राज्य नीति आयोग के ऋषि गर्ग,

आर्ट ऑफ लिविंग के विभिन्न कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों, वैज्ञानिकों, सशस्त्र बलों, पंचायती राज प्रतिनिधियों, युवाओं, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु विशेष रूप से बनाए गए हैं. संस्था जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, वनीकरण, नशा मुक्ति, जेल सुधार, सीमावर्ती गांव विकास जैसे क्षेत्रों में भी कार्य कर रही है. साथ ही आर्ट ऑफ लिविंग की विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों के साथ सक्रिय भागीदारी है.

आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के रोहन जैन, अजित भास्कर तथा अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे.

# मुख्यमंत्री यादव प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बाटेंगे लैपटॉप

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 1 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार 4 जुलाई को विद्यार्थियों को लैपटॉप बाटेंगे. भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे क्वेश्चन सेंटर में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में सीएम यादव लैपटॉप वितरित करेंगे. कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे.

स्कूल शिक्षा विभाग की प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक अर्जित करने

## 4 जुलाई को कुशाभाऊ ठाकरे क्वेश्चन सेंटर में होगा कार्यक्रम

वाले प्रति विद्यार्थी को 25 हजार रुपये की राशि लैपटॉप क्रय करने के लिये उनके बैंक खाते में अंतरित करेंगे. इस वर्ष 94 हजार 234 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिये 235 करोड़ 58 लाख 50 हजार रुपये की राशि दी जा रही है.

कार्यक्रम में 500 से अधिक विद्यार्थी और शिक्षक सहभागिता करेंगे. प्रदेश में पिछले वर्ष 2023-24 में 89 हजार 710 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक खातों में 224 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपये की राशि अंतरित की गयी थी.

## एक नजर में

एमपीयूडीसी का 'लोगो' तैयार पर मिलेगा पुरस्कार  
भोपाल. नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत संचालित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी ने क्रिएटिव इनिशिएटिव का शुभारंभ करते हुए एक शानदार 'लोगो' डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया है. यह पहल स्वच्छता पोर्टल के माध्यम से जन-भागीदारी को प्रेरित करने और कंपनी की शहरी सुधार योजनाओं, शहरों की सोवरेज, जलापूर्ति और अन्य अधोसंरचना से जुड़े कार्यों के प्रति जागरूकता व पहचान को बढ़ावा देने के लिये की गई है. प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आम नागरिकों को पोर्टल पर अपना मौलिक डिजाइन फॉर्मेट में अपलोड करना होगा.



## नौकरी पाने से खिले चेहरे

भोपाल, 1 जुलाई. ऊर्जा विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी में विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के भौतिक परीक्षण की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई. शासकीय सेवा में नियुक्ति का सपना साकार होने की संतुष्टि और उल्लास चयनित अभ्यर्थियों के चेहरों पर साफ झलक रहा था.

## मृत्यु के बाद जीवन का उपहार देना अमरता है

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देहदान या अंगदान करने वालों के परिजन को राज्य सरकार 26 जनवरी एवं 15 अगस्त के कार्यक्रमों में सम्मानित करेगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मृत्यु के बाद किसी को जीवन का उपहार देना सिर्फ दान नहीं, बल्कि यह अमरत्व प्रदान करने जैसा है. सामाजिक दृष्टि से यह पुण्य कार्य है मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि देहदान अथवा हृदय, लीवर व गुर्दा दान (डोनेट) करने वाले देहदानियों/अंगदानियों के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी.

# सोनम के डिवाइस से मिले चौंकाने वाले सबूत

हवाला रैकेट की परतें खोल रहा लैपटॉप

शिलांग पुलिस की पूछताछ में सामने आए कई राज  
सोनम के खुलासा से केस ने पकड़ नया मोड़



हवाला नेटवर्क में सोनम की सक्रिय भूमिका की पुष्टि अब तकनीकी सबूतों से हो चुकी है, जो अब कोर्ट में केस फाइल का हिस्सा बनने जा रहे हैं. शुरुआती जांच में इस पूरे नेटवर्क से जुड़े गोविंद ने हर बार हवाला केस से इनकार किया,

लेकिन सोनम ने पुलिस की पूछताछ में वह राज खोल दिए जो अब दस्तावेज और डिजिटल सबूतों के रूप में सामने आ चुके हैं. पुलिस ने सोनम से जब बरामद लैपटॉप और पेन ड्राइव को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा तो उनमें हवाला ट्रांजेक्शन से जुड़े कई इन्फॉर्मेटिव फाइलें, एक्सल शीट्स, संदिग्ध बैंक ट्रांजेक्शन की डिटेल्स और कोडवर्ड्स में हुई इमेल बातचीत सामने आई.

शिलांग पुलिस के सूत्र बताते हैं कि इन दस्तावेजों में कुछ ऐसे लेन-देन और नाम भी दर्ज हैं, जिनके तार देश के अलग-अलग हिस्सों से जुड़े बताए जा रहे हैं.

शिलांग पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि सोनम हवाला चैनल में न केवल मेसेंजर के रूप में बल्कि लॉजिस्टिक और ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग में भी सक्रिय भूमिका में थी. अब तक की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि हवाला के इस नेटवर्क में डिजिटल पैमेंट ऐस का उपयोग कर ट्रांजेक्शन को छिपाया जाता था और कई बार नकद रकम को अलग-अलग खातों में विभाजित कर ट्रांसफर किया जाता था, ताकि रकम ट्रेस न हो सके. पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क की जड़ें कुछ कारोबारियों और विदेशी लेन-देन से भी जुड़ी हो सकती हैं.

## खाद्य विभाग की दो दिवसीय कार्यशाला आज और कल

भोपाल. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 02 दिवसीय कार्यशाला 2 और 3 जुलाई को पलाश रैसीडेंसी में आयोजित की जा रही है. प्रशिक्षण में खाद्य विभाग, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सलाइज कॉरपोरेशन एवं मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के जिले एवं प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी सहभागिता करेंगे. कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण राधिका अरुण शर्मा, आयुक्त कर्मवीर शर्मा एवं नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक अनुराग वर्मा द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा.

# सीएम ने नायडू समेत मंत्रियों को दी बधाई

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्व उप राष्ट्रपति केंकेया नायडू को जन्म दिवस पर बधाई दी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्र के उन्नयन और समाज के उत्थान के लिए वरिष्ठ नेता नायडू की अद्वितीय कार्यशैली और ओजस्वी विचार सदैव देशवासियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल से नायडू के दीर्घायु जीवन एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है. इसके साथ ही मंत्रालय में केबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप

अहिरवार को जन्म दिवस पर पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में उपस्थित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत

## डाक कर्मियों के सेवा भाव को किया नमन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि डाक सेवा, सुविधा या व्यवस्था ही नहीं, बल्कि भारतीय नागरिकों को एक-दूसरे से जोड़ने का सशक्त माध्यम है. डाक विभाग के कर्मचारी विपरीत परिस्थिति, प्रतिकूल मौसम एवं अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी घर-घर तक पत्र, पार्सल और जरूरी दस्तावेज आदि पहुंचाने का कार्य करते हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देश के डाक कर्मचारियों को उनके सेवा भाव एवं समर्पण के लिए राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस पर उन्हें शुभकामनाएं दीं. वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश के आर्थिक विकास सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्वल भविष्य के लिए मंगलकामनाएं प्रेषित कीं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनसेवा के ध्येय के साथ प्रदेश के गरीब, वंचित और कमजोर वर्ग के कल्याण में अहम भूमिका निभा रहे चिकित्सकों के प्रति नेशनल डॉक्टर्स-डे पर कृतज्ञता व्यक्त की है.

को भी जन्म दिवस पर शुभकामनाएं दीं तथा मंत्रीगण को बताया कि पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और विधायक रीति पाठक का जन्म दिन भी है.

# स्पेशल ट्रेनें गया तक जाएंगी

रानी कमलापति सहित स्टेशनों पर होगा टहराव

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 1 जुलाई. रेल प्रशासन द्वारा स्पेशल ट्रेनों के संचालन के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए गाड़ी संख्या 01922 और 01921 वीरगंगा लक्ष्मीबाई झांसी सुपरफास्ट सामाहिक स्पेशल ट्रेन के संचालन को यात्रियों की बढ़ती मांग के मद्देनजर विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है.

इस स्पेशल ट्रेन के विस्तार से पश्चिम मध्य रेल के बीना, विदिशा, रानी कमलापति, नर्मदापुरम एवं इटारसी के स्टेशनों के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा.

गाड़ी संख्या 01922 वीरगंगा लक्ष्मीबाई झांसी-पुणे सामाहिक स्पेशल ट्रेन प्रत्येक बुधवार को वीरगंगा लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन से 02 जुलाई से 31 दिसंबर तक 27 फेरों के लिए चलती रहेगी. इसी प्रकार गाड़ी संख्या 01921 पुणे-वीरगंगा लक्ष्मीबाई झांसी सामाहिक स्पेशल ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को पुणे स्टेशन से 03 जुलाई 2025 से 01 जनवरी 2026 तक 27 फेरों के लिए किया जा रहा है. यह गाड़ी दोनों दिशाओं में ललितपुर, बीना, विदिशा, रानी कमलापति, नर्मदापुरम, इटारसी, खण्डवा, भुसावल, मनमाड, कोपरगांव, अहमदनगर एवं दौंड कॉर्ड लाइन पर टहराव लेती है.



# मंदसौर, नीमच में होगी झमाझम भारी बारिश

मौसम विभाग का आरंज अलर्ट जारी

40 किमी की रफ्तार से चलेगी हवा

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 1 जुलाई. मप्र के रतला, मंदसौर, नीमच जिलों में बुधवार को अत्यधिक बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने यहां भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है.

इसके साथ ही ग्वालियर, दतिया, श्योरपुरकला, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, विदिशा, राजगढ़, कटनी, जबलपुर, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में भी अति बारिश हो सकती है. इन जिलों में आरंज अलर्ट जारी किया गया है. रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, सीधी, रीवा, सिंगरौली सहित

जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेशभर के जिलों में अति बारिश को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान लगाया है. इस दौरान करीब 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. प्रदेश में 3 जुलाई तक झमाझम बारिश की संभावना जात है.

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी भाग तथा उससे संलग्न पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इससे संबंधित चक्रवाती परिस्वरण माध्य समुद्र तल से 7.6 किमी ऊपर तक फैला हुआ है. अगले 2 दिनों के दौरान इसके उत्तर ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है.

## लोक परिवहन

मप्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 तैयार, टैक्स में छूट और अनुदान मिलेगा

# प्रदेश के 6 शहरों में चलेंगी 582 इलेक्ट्रिक बसें

प्रशासनिक संवाददाता  
भोपाल, 1 जुलाई. प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिये मप्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी - 2025 तैयार की गई है. इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा परिवहन कर में छूट और अनुदान दिये जाने की भी व्यवस्था की गई है.

प्रदेश के 6 बड़े शहरों में 582 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा. वर्तमान में इंदौर में शहरी मार्गों पर 80 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है. फेम योजना के अंतर्गत 40



और अमृत योजना 1.0 में 40 बसें संचालित हो रही हैं.

ई-बस सेवा योजना के तहत 6 शहरों में 582 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिये प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया था, जिसे केन्द्रीय शहरी मंत्रालय ने दिल्ली

से स्वीकृति मिल गयी है. इंदौर में 150, भोपाल में 100, ग्वालियर में 100, जबलपुर में 100, सागर में 32 एवं उज्जैन में 100 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का प्रस्ताव है. प्रदेश के 6 शहरों में बस संचालन के लिये नगरीय

## 34 चार्जिंग स्टेशन पर 190 चार्जिंग पाइंट

नगरीय निकायों द्वारा बस डिपो एवं चार्जिंग स्टेशन निर्माण के लिये प्राकृतिक तैयार कर राज्य स्तरीय संचालन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है. अनुमोदन के बाद प्रस्ताव केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा गया है. भोपाल एवं जबलपुर शहर द्वारा बस डिपो अधोसंरचना निर्माण के लिये निविदा जारी की जा चुकी है. प्रदेश के शहरों में लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल के संचालन को बढ़ावा देने के लिये भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर शहर में 34 चार्जिंग स्टेशन पर 190 चार्जिंग पाइंट लगाये गये हैं.

विकास एवं आवास विभाग द्वारा निविदा जारी कर बस संचालकों का चयन किया जा चुका है. पीएम ई-बस सेवा के अंतर्गत बस डिपो अधोसंरचना निर्माण के लिये भी प्रस्ताव तैयार किया गया है, इसमें 60 प्रतिशत राशि

केन्द्र सरकार द्वारा और शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदाय की जायेगी. इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग अधोसंरचना निर्माण के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि प्रदान की जायेगी.